प्रेस को सूचना नोट [प्रेस विज्ञप्ति संख्या 29/2022]

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 7 मई 2022: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र जारी किया।

2. केबल टीवी क्षेत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अनुरूप, भादूविप्रा ने 3 मार्च 2017 को प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए 'नए नियामक ढांचे' को अधिसूचित किया। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच पारित करने के बाद नया ढांचा 29 दिसंबर 2018 से लागू हुआ।

3. नए विनियामक ढांचे 2017 के कार्यान्वयन पर, भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कुछ कमियों को देखा। जैसे ही नए विनियामक ढांचे ने कुछ व्यावसायिक नियमों को बदल दिया, कई सकारात्मक बातें सामने आईं। नए विनियामक ढांचे के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए, हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद,भादूविप्रा ने 01.01.2020 को नए विनियामक ढांचे 2020 को अधिसूचित किया।

4. कुछ हितधारकों ने बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय और केरल सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और सेवा की गुणवत्ता संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालयों ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर नए विनियामक ढांचे 2020 की वैधता को बरकरार रखा।

5. नए विनियामक ढांचे 2020 के नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी-टीवी होम और नए विनियामक ढांचे 2020 के लंबी अवधि की सब्सक्रिप्शन से संबंधित प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं को उचित लाभ दिए जा रहे हैं। प्रत्येक उपभोक्ता अब अधिकतम 130/- रुपये के एनसीएफ में 100 चैनलों के बजाय 228 टीवी चैनल प्राप्त कर सकता है।

इसने उपभोक्ताओं को 2017 के ढांचे के अनुसार समान संख्या में चैनलों का लाभ उठाने के लिए अपने एनसीएफ को 40/- रुपये से 50/- रुपये तक कम करने में सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, मल्टी-टीवी घरों के लिए संशोधित एनसीएफ ने दूसरे (और अधिक) टेलीविजन सेटों पर 60% की और बचत की है।

6. हालांकि, प्रसारकों द्वारा दायर किए गए आरआईओ के अनुसार, नए प्रशुल्क एक सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी, खेल के चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतें 20 रुपये प्रति माह से अधिक निर्धारित की गई। पे चैनलों को बुके में शामिल करने के संबंध में सीमा के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, 12/- रुपये प्रति माह से अधिक मूल्य वाले ऐसे सभी चैनलों को बुके से बाहर रखा गया है और केवल अ-ला-कार्टे आधार पर पेश किया गया है। दायर किए गए संशोधित आरआईओ लगभग सभी बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत देते हैं।

7. नए प्रशुल्क की घोषणा के तुरंत बाद, भादूविप्रा को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ), एसोसिएशन ऑफ लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। डीपीओ ने सिस्टम में नई दरों को लागू करने में और लगभग सभी बुके को प्रभावित करने वाले विकल्पों के सूचित अभ्यास के माध्यम से उपभोक्ताओं को नई प्रशुल्क व्यवस्था में स्थानांतरित करना, विशेष रूप से प्रसारकों द्वारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संशोधन के कारण उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। इसलिए, भादूविप्रा एलसीओ के प्रतिनिधियों सहित सभी विभिन्न संघों और उपभोक्ता समूहों के साथ विचार विमर्श किया।

8. नए विनियामक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए, भादूविप्रा के तत्वावधान में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया।

9. समिति का उद्देश्य प्रशुल्क संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक आम सहमति के रास्ते पर आने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच चर्चा की सुविधा प्रदान करना था। हितधारकों को सलाह दी गई थी कि वे नए विनियामक ढांचे 2020 को लागू करते समय उपभोक्ताओं को न्यूनतम व्यवधानों और बाधाओं के साथ एक कार्यान्वयन योजना के साथ सामने आएं।

10. समिति ने नए विनियामक ढांचे 2020 से संबंधित कई मुद्दों को उनपर सोच-विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया। हालाँकि, हितधारकों ने भादूविप्रा से उन महत्वपूर्ण मुद्दों को तुरंत दूर करने का अनुरोध किया जो प्रशुल्क संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए बाधाएं पैदा कर सकते हैं।

11. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए; प्राधिकरण इस परामर्श पत्र को नए नियामक ढांचे 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लंबित मुद्दों / मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए जारी कर रहा है। यह पत्र मुख्य रूप से बुके के निर्माण में दी गई छूट, बुके में शामिल करने के लिए चैनलों की अधिकतम कीमत, और वितरण शुल्क के अलावा डीपीओ को प्रसारकों द्वारा दी जाने वाली छूट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करता है।

12. परामर्श पत्र पर 30 मई 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, 6 जून 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं।

13. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष क्रमांक +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा